रोजगार देकर स्वावलम्बी बनाना हमारी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ सभी सम्भावनाओं को गति देने का प्रयास कर रही है। सभी को रोजगार देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां अपने सरकारी आवास पर नई एमएसएमई इकाइयों के लिए आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने 98743 नवीन इकाइयों को 2447 करोड़ के ऋण ऑनलाइन वितरित किये। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण योजना तथा ओडीओपी-विपणन प्रोत्साहन योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया का भी शुभारम्भ किया।

योगी ने कई योजनाओं का किया शुभारंभ

98743 नवीन एमएसएमई इकाइयों को 2447 करोड़ के ऋण ऑनलाइन वितरित किये

योगी के समक्ष प्रदेश में नॉलेज और टेक्नोलॉजी के आदान-प्रदान के उद्देश्य से एमएसएमई विभाग तथा एकेटीयू के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से ई-वे के साथ भी एमओयू अभिलेखों का आदान-प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने 'एक जनपद, एक उत्पाद योजना' के तहत 13 कॉमन फैसिलिटी सेण्टर का शिलान्यास तथा प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एसाइड/निर्यात अवस्थापना योजना के अन्तर्गत 6 सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) का लोकार्पण किया।

उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों-प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम, 'एक जनपद, एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों को चेक भेंट किये। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जब आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हैं, तब इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के अलग-अलग तबके के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने आर्थिक पैकेज का बेहतर उपयोग किया है। इसके माध्यम से उद्यमियों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया जा रहा है। योगी ने कहा कि प्रदेश के स्थानीय पारम्परिक उद्योगों को आगे बढ़ाने तथा छोटे उद्योगों को एक क्लस्टर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 'एक जनपद, एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत क्लस्टर में पारम्परिक उद्योगों को कॉमन फैसिलिटी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गयी है। इस उद्देश्य से कॉमन फैसिलिटी सेण्टर का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सामान्य सुविधा केन्द्रों से सम्बन्धित प्रवर्तक तथा सुविधा केन्द्रों का संचालन करने वाली संस्थाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सम्भावनाओं वाला प्रदेश है। प्रदेश के नौजवानों को स्वावलम्बी बनाकर उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे प्रदेश का नवनिर्माण होगा। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 में भी सम्भावनाओं को तलाश रही है। इसके दृष्टिगत एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों को ऋण वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री उदयभान सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम नवनीत सहगल, एकेटीयू के वीसी प्रो. विनय कुमार पाठक सहित विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी उपस्थित थे।